Use of polyurethane foam as cushioning material

1918. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY:

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that polyu-rethane foam used as cushioning material in items of furniture, continues to find a growing market in India although it has been banned in Western countries; and

(b) if s°i what steps Government have taken to prevent the use of this foam for furniture and matresses?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) Use of Polyurethane foam has not been banned in Western countries, Polyurethane foam used as cushioning material in items of furniture per se is not toxic but the possibility of toxic emission cannot be ruled out if foam is ignited in absence of abundant oxygen.

Measures to revive the sick public sector units

1919. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1230 given in the Rajya Sabha on the 7th March, 1988 and state:

fa) what are the details of the measures suggested by the Prime Minister to revive the public sector units which are running in losses; and

(b) how many public sector units have been considered to be not viable and are closed together with the names thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO); (a) Reply to Unstarred Question No. 1230 given in the Rajya Sabha on the 7th March, 1988 relate to selling of equity shares of the Public Sector Undertakings and is not related to measures suggested by the Prime Minister to revive the public sector units which are running in losses.

(b) No Public Sector Unit has been closed so far.

DISC Antenna System for Television Transmission

1920. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are awwe of the fact that Disc Antenna System for television transmission is used in hundreds of villages in the country without legal permission; and

(b) if so, what are the details thereof and what action is being taken against such illegal use?

THE MINKfTER OF ENERGY AND THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI VASANT SATHE : (a) and (b) A licence is required for operation, possession and dealing etc. of a TV|VCR for reception of television programme from Indian satellite (INSAT). The licence fee is Rs. 10/- per year for

a user and Rs- 200|- per yea$_r$ for a dealer. Government not aware of any illegal use. However action can be taken under the provisions of Indian Telegraph Act, if any case of illegal use comes to notice.

सीमेंट डीलरों को सम्हलाई कमीशन

@1921. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में "लेवी" सीमेंट की बिक्री करने पर सीमेंट के डीलरों को प्रति बोरी कितना सम्हलाई कमीशन दिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली के शाहदरा और कालका जी क्षेत्र के सीमेंट डीलरों को ढुलाई उच्च प्रभार की वजह से हानि हो रही है ;

(ग) क्या सरकार "लेवी" सीमेंट के इन डीलरों को दिये जाने वाले सम्हलाई कमीशन को बढ़ाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के खंड 10 के अनुसार, सीमेंट का अधिकतम मूल्य जिस पर किसी डीलर (थोक अथवा खुदरा) द्वारा सीमेंट बेचा जा सकता है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और कोई भी डीलर थोक अथवा खुदरा) इस अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर सीमेंट नहीं बेचेगा । अधिकतम मूल्य का निर्धारण करने में राज्य सरकार (i) सीमेंट नियंत्रण आदेश के खंड 8 के अन्तर्गत निर्धारित किए गए मूल्य अर्थात् सीमेंट की संबंधित किस्म का एफ. ओ. आर. मूल्य, (ii) सम्हलाई (पैकिंग या कन्टेनर से संबंधित प्रभारों सहित) और ढुलाई प्रभारों, (iii) गोदाम प्रभारों, (iv) भंडारकर्ताओं के लाभांश (v) स्थानीय करों, यदि कोई हों, (vi) अतिरिक्त मार्ग परिवहन प्रभारों, जहां स्वीकार्य हों, पर उचित ध्यान देगी । बशर्ते की वस्तुओं की सम्हलाई (पैकिंग कन्टेनर से संबंधित प्रभारों सहित) तथा ढुलाई प्रभारों, गोदाम प्रभारों और भण्डार कर्ताओं के लाभांश के संबंध में निर्धारित किया जाने वाला कुल प्रभार 50 रु० प्रति टन से अधिक नहीं होगा ।

दिल्ली प्रशासन किसी सीमेंट डीलर को प्रति मी. टन निम्नलिखित कमीशन/ प्रभार की अनुमति दे रहा है :—

	रु०
1. रेलवे स्टेशन पर सम्हलाई प्रभार . .	2.50
2. लदान/उतरान तथा गोदामों में रखने के प्रभारों सहित ढुलाई प्रभार . .	12.00
3. गोदाम किराया . .	2.50
लाभांश . .	11.00
कुल .	28.00

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) से (ङ) दिल्ली के सीमेंट भण्डारकर्ताओं ने सूची की बिक्री के लिए

@Previously Unstarred Question 1665 transferred from the 11th March, 1988.